दिनांकः 27.11.2024 समय : 01:00 पी.एम.

प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी जयपुर–अजमेर

केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बाल विवाह की कुरीति को समाप्त करने के उद्देश्य से कार्य योजना तैयार को कहा है। आज नई दिल्ली से राष्ट्रीय अभियान–बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बाल विवाह को समाप्त करने और बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अभियान के दौरान सबसे अधिक प्रभावित लगभग 300 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी के सामूहिक प्रयासों से लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।
कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल की भी शुरूआत हुई। ये प्लेटफॉर्म जागरुकता बढ़ाने, बाल विवाह रोकने और ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना देने के मिशन में सहयोग के लिए शुरू किया गया है।
प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर इस अभियान के तहत बाल विवाह के विरुद्ध शपथ कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। श्रीगंगानगर के स्वास्थ्य भवन में सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला और एसीएमएचओ डॉ. मुकेश मेहता ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। गौरतलब है कि बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का प्राथमिक लक्ष्य देश को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्ति दिलाना है।

000

राज्य के विमुक्त और घुमन्तु समुदाय के लोगों के आवश्यक दस्तावेज बनाने के लिए आज से सभी जिलों में शिविर लगाए जा रहे हैं। पंचायत समितियों, नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद स्तर पर ये शिविर 15 दिसम्बर तक आयोजित किये जाएंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि इन शिविरों के लिए संबंधित प्रभारी, उपखण्ड अधिकारी होंगे। शिविरों के दौरान इस समुदाय के लोगों के वोटर आई.डी. आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और घुमन्तु पहचान प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज बनाए जाएंगे। श्री गहलोत ने बातया कि इन लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ने के लिए शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

000

प्रदेशभर में अब राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा–रीट का आयोजन एक ही दिन में किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव, कृष्ण कुणाल ने ये जानकारी दी। रीट को लेकर कल जयपुर के शिक्षा संकुल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री कुणाल ने बताया कि अभ्यर्थियों को उनके निकटतम जिलों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने पर भी विचार किया गया है। उन्होंने परीक्षा की गोपनीयता और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिये। शासन सचिव ने परीक्षा का आयोजन फरवरी में करवाने के साथ ही प्रश्न पत्र बनाने, रख–रखाव तथा वितरण व्यवस्था में पूरी सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने परीक्षा के सुचारू और सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिए।

000

राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 17 दिसम्बर से शुरू होंगी। ये परीक्षाएं 27 दिसम्बर तक चलेंगी। वहीं प्रायोगिक परीक्षाएं 12 से 16 दिसम्बर के बीच आयोजित की जाएंगी। राज्य में पहली बार एक साथ हो रहीं इन परीक्षाओं की समय सारिणी जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने कहा कि इस बार सर्दी की छुट्टियां 25 दिसम्बर से शुरू नहीं होंगी। गौरतलब है कि अब तक समान परीक्षा जिला स्तर पर होती थीं, जिसके लिए जिले के किसी एक स्कूल को जिम्मा सौंपा जाता था। प्रश्न पत्र भी जिला स्तर पर ही तैयार किये जाते थे। लेकिन, अब राज्यभर में एक ही प्रश्न पत्र से परीक्षा होगी।

000

मेहरम के साथ हजयात्रा पर जाने की इच्छुक महिलाओं के लिए हज कमेटी ऑफ इण्डिया ने 500 सीटें आवंटित की हैं। यह उन महिलाओं के लिए हज पर जाने का स्वर्णिम अवसर है, जिनके मेहरम का तो हज 2025 के लिए चयन हो गया है, लेकिन किसी कारणवश महिलाओं का चयन नहीं हो पाया है। राजस्थान स्टेट हज कमेटीके अधिशाषी अधिकारी अबु सुफियान चौहान ने बताया कि इच्छुक महिलाएं इसके लिए 9 दिसम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि 500 से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में डिजिटल रेण्डम सेलेक्शन प्रोसिजर द्वारा चयन किया जाएगा। हज 2025 की दूसरी किस्त 16 दिसम्बर तक जमा कराना आवश्यक है।

000